नारी केवल एक व्यक्तित्व नहीं है; वह मूल्य है, संस्कृति है और शक्ति का सजीव स्वरूप है: नमिता ममगाई

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

15th ANNIVERSARY

वर्ष 15 | अंक 41 | मूल्य 05 रुपये | 01-07 मार्च, 2026

सुरक्षित और स्मार्ट होगी चारधाम यात्रा

शिक्षा की किताब में अदालत पर सवाल

होली के रंगों में क्या थमेगा सियासी बयानबाजी का तूफान

के संयुक्त तत्वावधान में

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

कॉन्क्लेव एवं सम्मान समारोह

पांचवा विज्ञान प्रयोगधर्मी महिला सम्मान- 2026

आठवां हिमालयी नारी शक्ति सम्मान- 2026

समारोह में आप सादर आमंत्रित हैं।

दिनांक एवं समयः
शनिवार, 07 मार्च, 2026
प्रातः 11.00 बजे

YOUNG WOMEN SCIENTIST

आयोजन स्थलः
इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, ऑडिटोरीअम,
निकट आईएसबीटी चौक, सहारनपुर रोड, देहरादून

दिव्य हिमगिरि

01-07 मार्च, 2026

संपादक
डॉ. कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

संवाददाता
पूनम आर्या

विज्ञापन
सुनील सेमवाल

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार: डॉ. रजनीश गौतम
पौडी: रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार: के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर: हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली: मुकेश रावत
रुड़की: श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल: शीतल तिवारी
अल्मोड़ा: संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर: अजय शर्मा
प्रसार: रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा आईशा प्रिंटिंग प्रेस, 292/1, चुक्खूवाला, ओंकार रोड, देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*

*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

राजनीति, गिरफ्तारी और बरी: शराब नीति प्रकरण से उठते गंभीर सवाल

दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले में विशेष अदालत का हालिया फैसला केवल एक मामले का न्यायिक निष्कर्ष भर नहीं है, बल्कि यह देश की प्रमुख जांच एजेंसियों-केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यप्रणाली पर फिर से गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। अदालत द्वारा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किए जाने से यह बहस तेज हो गई है कि क्या इन एजेंसियों की जांच निष्पक्ष और पेशेवर मानकों पर खरी उतर रही है, या फिर वे किसी दबाव अथवा पूर्वाग्रह से प्रभावित होकर कार्रवाई कर रही हैं। यह मामला वर्ष 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा था, जिसे सरकार ने राजस्व बढ़ाने और शराब कारोबार में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लागू किया था। बाद में इस नीति में अनियमितताओं के आरोप लगे और जांच सीबीआइ को सौंपी गई। इसके पश्चात ईडी भी जांच में शामिल हुई और आरोप लगाया गया कि नीति के माध्यम से निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसी आधार पर कई गिरफ्तारियां हुई और राजनीतिक हलकों में तीखी बयानबाजी का दौर चला। किन्तु लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि आरोपों के समर्थन में ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। अदालत की यह टिप्पणी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जांच एजेंसी ने अनुमानों के आधार पर साजिश की कहानी गढ़ने का प्रयास किया। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी से अपेक्षा की जाती है कि वह तथ्यों, साक्ष्यों और विधिक कसौटियों पर पूरी तरह खरी उतरे। पिछले कुछ वर्षों में ईडी और सीबीआइ की भूमिका को लेकर राजनीतिक विमर्श में लगातार आरोप लगते रहे हैं कि इनका इस्तेमाल विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। यह भी चिंता जताई जाती रही है कि एजेंसियों की सक्रियता का पैटर्न राजनीतिक घटनाक्रम से मेल खाता दिखाई देता है। यद्यपि ऐसे आरोपों की सत्यता का निर्धारण न्यायालयों के माध्यम से ही संभव है, परंतु बार-बार उठते प्रश्न संस्थागत विश्वसनीयता को प्रभावित अवश्य करते हैं। यह भी तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जांच एजेंसियों के कामकाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट को भी समय-समय पर सख्त टिप्पणियां करनी पड़ी हैं। शीर्ष अदालत ने एजेंसियों को निष्पक्षता, पारदर्शिता और विधिसम्मत प्रक्रिया के पालन की याद दिलाई है। जब न्यायपालिका इस स्तर पर चिंता प्रकट करे, तो यह संकेत है कि सुधार की आवश्यकता को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोषसिद्धि की दर का है। यदि बड़ी संख्या में मामले दर्ज हों, व्यापक गिरफ्तारियां हों, परंतु अंततः अदालत में आरोप टिक न पाएं, तो यह आत्ममंथन का विषय बनता है। क्या जांच प्रक्रिया में पर्याप्त तैयारी और साक्ष्य-संग्रह हो रहा है? क्या आरोपपत्रों की विधिक जांच पर्याप्त रूप से की जाती है? या फिर राजनीतिक और सार्वजनिक दबाव के चलते जल्दबाजी में कदम उठाए जाते हैं? दिल्ली शराब नीति प्रकरण से जो सबसे बड़ा सबक सामने आता है, वह यह है कि कानून का शासन केवल आरोप लगाने से स्थापित नहीं होता; उसे प्रमाणित करने की क्षमता और निष्पक्षता से ही बल मिलता है। जांच एजेंसियों को यह समझना होगा कि उनकी हर कार्रवाई लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता से जुड़ी होती है।

डॉ. कुँवर राज अस्थाना

नारी केवल एक व्यक्तित्व नहीं है; वह मूल्य है, संस्कृति है और शक्ति का सजीव स्वरूप है: नमिता ममगाई

बाल कल्याण समिति, देहरादून की अध्यक्षा नमिता ममगाई से पूनम आर्य की खास बातचीत

पारिवारिक पृष्ठभूमि और शैक्षिक यात्रा

नमिता ममगाई एक शिक्षित एवं प्रगतिशील परिवार से संबंध रखती हैं, जहाँ शिक्षा को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उनके पिता ने वर्ष 1955 में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग में एम.टेक. की उपाधि प्राप्त की तथा बाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित सेवाएँ प्रदान कीं। उनकी माता स्नातक शिक्षित एवं सुसंस्कृत गृहिण ी रहीं, जिन्होंने परिवार को सुदृढ़ मूल्यों और संस्कारों से समृद्ध किया।

संयुक्त परिवार में पली-बढ़ी नमिता जी के परिवार में पुत्र और पुत्री के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। उन्हें अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिली। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में हुई तथा आगे की पढ़ाई सहारनपुर से पूर्ण कर उन्होंने स्नातक उपाधि अर्जित की। उन्नीस वर्ष की आयु में विवाह के पश्चात भी उनकी शिक्षा-यात्रा नहीं रुकी। उनके पति जे.पी. ममगाई ने सदैव उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया। मातृत्व की जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने बी.एड. की उपाधि प्राप्त की, जब उनकी पुत्री मात्र पाँच-छह माह की थी-जो उनके दृढ़ निश्चय और समर्पण का प्रतीक है।

इसके पश्चात उन्होंने निरंतर विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन किया-

ज्योतिष में डिप्लोमा, पत्रकारिता में डिप्लोमा, डोएक से 'ओ' लेवल कंप्यूटर कोर्स, एम.एड., एम.एससी. (भौतिकी), वर्ष 2023 में एलएलबी पूर्ण कर ऑल इंडिया बार एग्जाम उत्तीर्ण किया

उनके लिए शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन की आजीवन साधना है।

प्रोफेशन में आगमन एवं प्रेरणा स्रोत

शिक्षण उनके लिए केवल पेशा नहीं, बल्कि बचपन से जुड़ा स्वाभाविक आहवान रहा है। ग्रीष्मावकाश के दौरान वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की परिसर में वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 'समर कैंप' आयोजित करती थी, जहाँ वह उन्हें मूलभूत शिक्षा एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों से परिचित कराती थी।

वर्ष 1980 में बारहवीं कक्षा में उन्होंने 82 प्रतिशत अंकों के साथ पाँचों विषयों में विशिष्टता प्राप्त की। वह इस सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों को देती हैं। बी.एड. के पश्चात उन्होंने लगभग 35 वर्षों तक शिक्षण कार्य किया। दिल्ली स्थित एयरफोर्स स्कूल में लगभग 25 वर्षों तक भौतिकी का अध्यापन किया। वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भी जुड़ी रही, जहाँ कक्षा 10 के विज्ञान प्रश्नपत्र निर्माण एवं मूल्यांकन में योगदान दिया। 'सतत और व्यापक मूल्यांकन (सीसीई)' योजना के अंतर्गत मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य कर अनेक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के साथ उन्होंने विज्ञान विषय की पुस्तकों के लेखन एवं प्रशिक्षण कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई।

संस्थान पुनर्जीवन की प्रेरक कहानी

वर्ष 2023 में उन्होंने बी.एस. नेगी महिला प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान की ऑनरेरी प्रिंसिपल के रूप में जिम्मेदारी संभाली। आर्थिक एवं प्रशासनिक चुनौतियों से जूझ रहे इस संस्थान में छात्रसंख्या अत्यंत सीमित

थी। उनके प्रयासों से दो से ढ़ाई वर्षों में छात्रसंख्या 48 से बढ़कर लगभग 300 तक पहुँच गई। आज यहाँ फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, पीजीडीसीए, बीएससी आईटी एवं बीएफडी जैसे कौशल-आधारित पाठयक्रम संचालित हो रहे हैं। अधिकांश छात्राएँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं, जिन्हें प्रायोजन के माध्यम से नि:शुल्क शिक्षा दी जा रही है।

प्रमुख उपलब्धियाँ

उन्होंने विद्यालय में 'खगोल विज्ञान क्लब' की स्थापना की और खगोल विज्ञान को व्यवहारिक अनुभव से जोड़ा। विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त की तथा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहभागिता की। उन्होंने 'मिशन आविष्कार' नामक अंतर-विद्यालयी विज्ञान प्रतियोगिता की स्थापना की, जिसमें लगभग 70-75 विद्यालयों के विद्यार्थियों को मंच मिला।

अप्रैल 2025 में उन्हें उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत बाल कल्याण समिति, देहरादून की अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया। समिति का उद्देश्य परित्यक्त, संरक्षण की आवश्यकता वाले एवं पॉक्सो पीड़ित बच्चों के पुनर्वास एवं संरक्षण को सुनिश्चित करना है।

सम्मान एवं पुरस्कार

उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान (2023), नारी शक्ति सम्मान (2025)-यूएसईआरसी, सुषमा स्वराज पुरस्कार, रोटरी क्लब प्रशंसा प्रमाण पत्र, राष्ट्र निर्माता पुरस्कार-2025, प्रोफेशनल एक्सीलेंस अवॉर्ड-2025 (माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदान)

भविष्य की योजना

वह वर्तमान में ऑनरेरी प्रिंसिपल के रूप में पूर्णत: प्रो-बोनो (नि:शुल्क) सेवा दे रही हैं। उनका लक्ष्य आगामी तीन वर्षों में 300 से 6020 छात्राओं तक कौशल-आधारित शिक्षा पहुँचाना है।

वह "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ", "स्किल इंडिया", "मेक इन इंडिया" तथा "विकसित भारत 2047" के संकल्प में सक्रिय योगदान देना चाहती हैं।

उनका विश्वास है- "शिक्षा केवल ज्ञानार्जन नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का माध्यम है।"

दिव्य हिमगिरि के माध्यम से संदेश

दिव्य हिमगिरी जैसी प्रेरणादायक पत्रिका के माध्यम से मैं अपनी समस्त बेटियों और युवतियों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि वह अपने सपनों को कभी सीमित न करें। बड़े लक्ष्यों से भयभीत न हों, बल्कि आत्मविश्वास के साथ स्वयं से कहें-

"मैं यह कर सकती हूँ।" किसी भी पेशे का कोई जेंडर नहीं होता। सफलता का निर्धारण लिंग से नहीं, बल्कि योग्यता, परिश्रम और दृढ़ संकल्प से होता है। हमारे पॉलिटेक्निक का मूल मंत्र भी यही है-

"Only I can change my life."

अर्थात अपने जीवन को बदलने की शक्ति केवल मेरे भीतर है।

जब एक बेटी स्वयं यह निर्णय लेती है कि उसके लिए क्या उचित है, और वह अडिग निश्चय के साथ आगे बढ़ती है, तभी उसके जीवन का मार्ग वास्तव में प्रशस्त होता है। मैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की भावना को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहती हूँ कि जब एक बेटी शिक्षित होती है, तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित नहीं होता-पूरा परिवार शिक्षित होता है। समाज जागरूक होता है और राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर होता है।

नारी केवल एक व्यक्तित्व नहीं है; वह मूल्य है, संस्कृति है और शक्ति का सजीव स्वरूप है-

नारी मान है, सम्मान है,
नारी हमारी संस्कृति की शान है।
नारी शक्ति है, भक्ति है,
नारी ही जीवन-ज्योति की अभिव्यक्ति है।

मैं अपनी बेटियों से कहना चाहूँगी-

कम नहीं हो किसी से, यह सिद्ध करके दिखाओ। बंधनों को तोड़ दो, सीमाओं को पीछे छोड़ दो। सपनों को पंख दो और हर मंजिल को अपना बनाओ। आप सभी अपने आत्मविश्वास को अपनी पहचान बनाइए, परिश्रम को अपनी आदत बनाइए और सकारात्मक सोच को अपनी दिशा बनाइए।

जब एक बेटी आगे बढ़ती है, तो केवल उसका भविष्य नहीं बदलता-एक पूरी पीढ़ी का भविष्य बदलता है।

इसी विश्वास और मंगलकामना के साथ आप जीवन की ऊँचाइयों को प्राप्त करें और अपने सपनों को साकार करें।

दिव्य हिमगिरि

के प्रकाशन के संबंध में सूचना

फार्म- 4

(नियम 8 देखिए)

1. प्रकाशन स्थान	-	देहरादून (उत्तराखंड)
2. प्रकाशन अवधि	-	साप्ताहिक
3. मुद्रक का नाम	-	कुँवर बहादुर अस्थाना
क्या भारत का नागरिक है?	-	हां
पता	-	19, आदर्श विहार, रायपुर रोड, देहरादून।
4. प्रकाशक का नाम	-	कुँवर बहादुर अस्थाना
क्या भारत का नागरिक है?	-	हां
पता	-	19, आदर्श विहार, रायपुर रोड, देहरादून।
5. संपादक का नाम	-	कुँवर बहादुर अस्थाना
क्या भारत का नागरिक है?	-	हां
पता	-	19 आदर्श विहार, रायपुर रोड, देहरादून।
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो सामाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।	-	----------

मैं **कुँवर बहादुर अस्थाना** एतद् घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण मान्य हैं।

दिनाक:- 01 मार्च, 2026 ***ह. कुँवर बहादुर अस्थाना***

प्रकाशक

उपभोक्ता कानून में शीघ्र न्याय दिला सकती है कृत्रिम बुद्धिमत्ता!

डॉ श्रीगोपाल नारसन एडवोकेट

उपभोक्ता कानून में एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) का उपयोग रियल-टाइम डेटा विश्लेषण द्वारा खरीदारी के पैटर्न को समझने, शिकायतों के तेजी से निपटान, और क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी को रोकने के लिए किया जा रहा है। यह तकनीक उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता पर नजर रखने में सहायक सिद्ध हो रही है। उपभोक्ता मंत्रालय उपभोक्ताओं की शिकायतो को सुनने और उसका समाधान देने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है। एआई के कारण शीघ्र समाधान के चलते डिजिटल शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। एआई का उपभोक्ता कानून में उपयोग सन 2023 में पहली बार शुरू किया गया था। आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ. पुष्पक भट्टाचार्य और उनकी की टीम ने यह चैटबॉट तैयार किया है। साथ ही एनएलएसआईयू बेंगलुरु के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. राहुल हेमराजानी और उनकी टीम ने कानूनी पहलुओं को जोड़ते हुए इस चौटबॉट को प्रशिक्षित किया। डॉ. पुष्पक भट्टाचार्य और डॉ. राहुल हेमराजानी के इस प्रोजेक्ट में उपभोक्ता मंत्रालय नॉलेज पार्टनर था। उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान में एआई बेहद कारगर है। इसी के कारण उपभोक्ता शिकायतों की संख्या व समाधान में इजाफा हुआ है। आंकड़ो पर गौर करे तो दिसंबर, 2015 देश में जहां 12,553 उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज हुई थीं, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 1,55,138 हो गई है। सन 2023 में इन शिकायतों के समाधान में सामान्यत: 66.26 दिन लगते थे, जबकि सन 2025 में यह अवधि घटकर 48 दिन रह गई। वही जिन कंपनियों के खिलाफ शिकायतें अधिक होती हैं, उनको 'कन्वर्जेंस पार्टनर' बनाया जाता है। सन 2017 में ऐसी कंपनियों की संख्या 263 थी, जो कि अब बढ़कर 1,038 हो गई हैं। एआई बेस प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद ये कंपनियां उपभोक्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता दे रही हैं। देश में 53 प्रतिशत से अधिक लोग ऐसे हैं, जो सरकारी पोर्टल का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे में एआई चैटबॉट उनकी मदद करेगा। हाल ही में गपशप प्लेटफॉर्म ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर जागृति एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, जो उपभोक्ताओं के लिए मील का पत्थर है। कानून के क्षेत्र में एआई 'न्याय गुरु' देश का पहला एआई आधारित लीगल चैटबॉट है। यह लोगों को न सिर्फ ऑनलाइन कानूनी सलाह देता है, बल्कि कानूनी तौर पर उनके अधिकारों को समझने में मदद भी करता है। इसके लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर होमपेज पर चैटबॉट का आइकन पर क्लिक करना होगा। इस एआई चैटबॉट पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है। चैटबॉट आपकी शिकायत के आधार पर कानूनी दस्तावेज, नोटिस या आवेदन तैयार करने में सहायता करता है।

'ग्राहक न्याय' का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान प्रदान करना है। उपभोक्ता मंत्रालय राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सशक्त बना रहा है जिससे उपभोक्ता शिकायतों का समाधान 45 दिनों की बजाय सिर्फ 7 दिनों में हो सकेगा। उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो और कानूनी मेट्रोलॉजी नियमित रूप से बाजार का सर्वेक्षण करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में मद्द मिलती है। इसलिए हम कह सकते है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआई उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने में न सिर्फ मददगार है बल्कि नए जमाने मे शीघ्र,सुलभ व सस्ते न्याय का माध्यम भी बन रहा है।

(लेखक उत्तराखंड उपभोक्ता राज्य आयोग के वरिष्ठ अधिवक्ता है)

होली के रंगों में क्या थमेगा सियासी बयानबाजी का तूफान

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों असाधारण उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। "डांस-बार" वीडियो विवाद से शुरू हुआ सियासी तूफान अब खुले आरोप-प्रत्यारोप, प्रेस वार और सार्वजनिक बयानबाजी तक पहुंच चुका है। सत्ता और विपक्ष आमने-सामने हैं, पुराने मुद्दे फिर से उछाले जा रहे हैं और चुनावी साल से पहले माहौल लगातार गरमाता जा रहा है। इसी बीच ९ मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसे आगामी चुनावों से पहले धामी सरकार का महत्वपूर्ण पूर्ण बजट सत्र माना जा रहा है। साफ है कि सदन के भीतर भी तीखी बहस और टकराव के आसार हैं। ऐसे संवेदनशील राजनीतिक माहौल में होली ने रंग, मेल-मिलाप और आपसी सौहार्द्र का प्रतीक बनकर दस्तक दी है । अब सवाल यह है कि क्या होली के रंग नेताओं के बीच बढ़ती दूरियों और बयानबाजी के तूफान को कुछ देर के लिए थाम पाएंगे, या फिर सियासत की गर्मी त्योहार की मिठास पर भारी पड़ेगी? प्रदेश की निगाहें अब रंगों और राजनीति दोनों पर टिकी हैं।

उत्तराखंड, जिसे देवभूमि की पहचान, शांत राजनीतिक संस्कृति और अपेक्षाकृत संयमित सार्वजनिक जीवन के लिए जाना जाता रहा है, इन दिनों तीखी सियासी बयानबाजी और पुराने विवादों की वापसी से घिरा हुआ है। चुनावी साल की आहट के साथ राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है। आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला ऐसा तेज हुआ है कि विकास, नीति और जनहित जैसे मुद्दे पीछे छूटते दिखाई दे रहे हैं, जबकि निजी आरोप, पुराने वीडियो और व्यक्तिगत हमले चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। राज्य में एक पुराने "डांस-बार" वीडियो को लेकर उठे विवाद ने राजनीतिक माहौल को और अधिक गरमा दिया। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों और विभिन्न नेताओं ने एक-दूसरे पर तीखे आरोप लगाए। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि चुनाव से पहले माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए पुराने प्रकरणों को फिर से सामने लाया जा रहा है। सबसे पहले इस पूरे विवाद को हवा देने वालों में पूर्व विधायक प्रणव चौंपियन का नाम प्रमुखता से सामने आया। उन्होंने सार्वजनिक मंचों और मीडिया के माध्यम से कई भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना रहा कि सत्ता में बैठे कुछ लोग नैतिकता की बात तो करते हैं, लेकिन उनके अपने आचरण पर सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य की राजनीतिक संस्कृति को जानबूझकर विवादों में उलझाया जा रहा है ताकि वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत भी खुलकर सामने आए। उन्होंने न केवल वीडियो विवाद को गंभीर बताया, बल्कि सरकार की कार्यशैली पर भी प्रश्नचिह्न लगाया। उनका आरोप रहा कि राज्य में प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता की कमी है और कई मामलों में राजनीतिक संरक्षण के कारण जांच की दिशा प्रभावित होती

है। हरक सिंह रावत ने यह भी कहा कि यदि राजनीतिक नेतृत्व स्वयं विवादों में घिरा रहेगा तो प्रदेश की छवि राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल होगी।

दोनों नेताओं की बयानबाजी यहीं तक सीमित नहीं रही। उन्होंने कई मौकों पर भाजपा के विभिन्न नेताओं के पुराने प्रकरणों का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनाव से पहले जनता को "सच्चाई" जानने का अधिकार है। उनके आरोपों में नैतिक आचरण, प्रशासनिक निर्णयों और व्यक्तिगत व्यवहार तक के मुद्दे शामिल रहे। भाजपा नेताओं ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि यह एक पुराना और संदर्भ से काटकर पेश किया गया वीडियो है, जिसे चुनाव से ठीक पहले जानबूझकर उछाला जा रहा है। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी राजनीतिक लाभ के लिए व्यक्तिगत जीवन से जुड़े मामलों को सार्वजनिक बहस का विषय बना रहे हैं। भाजपा का यह भी कहना है कि यदि किसी प्रकार की शिकायत है तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि मीडिया ट्रायल के जरिए।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी दलों से संयम बरतने की अपील की। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड की राजनीति हमेशा अपेक्षाकृत शालीन रही है और व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप से राज्य की छवि को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने सुझाव दिया कि चुनावी बहस विकास, रोजगार और जनहित के मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। फिलहाल, वीडियो की सत्यता और संदर्भ को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन स्पष्ट है कि इस मुद्दे ने चुनावी माहौल को गरमा दिया है। आरोप और जवाबी आरोपों के बीच राजनीतिक दल अपने-अपने समर्थकों को साधने में जुटे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि मामला जांच की दिशा में बढ़ता है या चुनावी बयानबाजी तक ही सीमित रहता है।

यह केवल व्यक्तिगत आरोपों का मामला नहीं है, बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा भी है। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हर दल अपने प्रतिद्वंद्वियों को रक्षात्मक मुद्रा में लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पुराने विवादों को दोबारा उछालना एक सोची-समझी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, इस तीखी बयानबाजी का असर केवल नेताओं तक सीमित नहीं है। आम जनता के बीच भी राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ता दिखाई दे रहा है। सामाजिक मंचों पर बहसें तेज हैं, समर्थक और विरोधी आमने-सामने हैं, और प्रदेश की छवि पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उत्तराखंड, जो पर्यटन, आध्यात्म और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, वहां लगातार विवादों की सुर्खियां राज्य की सकारात्मक पहचान को प्रभावित कर रही हैं। इसी बीच राज्य की धामी सरकार का 9 मार्च से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। चुनाव से पहले यह पूर्ण बजट सत्र होगा, इसलिए इसकी राजनीतिक महत्ता और भी बढ़ गई है। विपक्ष ने साफ संकेत दिए हैं कि वह सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के लिए पूरी तैयारी में है। माना जा रहा है कि सदन के भीतर भी तीखी बहस और टकराव देखने को मिल सकता है।

यशपाल आर्य का धामी सरकार पर हमला, 21 दिन का सत्र कराने की मांग

उत्तराखंड में 9 मार्च से शुरू होने जा रहे बजट सत्र से पहले ही राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सत्ता पक्ष एक बार फिर विपक्ष के सवालों से बचने की रणनीति बना चुका है। उनका कहना है कि अब तक विधानसभा के कार्यकाल में कुल 32 कार्य दिवस ही हुए हैं, जो यह दर्शाता है कि सरकार सदन में जवाबदेही से बचना चाहती है। यशपाल आर्य ने कहा कि सोमवार का दिन परंपरागत रूप से मुख्यमंत्री के प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है, लेकिन उसे पूर्ण कार्य दिवस के रूप में शामिल नहीं किया जाता। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री के पास 40 महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है, तो विपक्ष को उन विभागों से जुड़े सवाल पूछने का पूरा अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा। उनका आरोप है कि सरकार जानबूझकर सत्र की अवधि सीमित रखती है ताकि गंभीर मुद्दों पर चर्चा से बचा जा सके।आर्य ने कहा कि 9 मार्च को गैरसैंण में राज्यपाल का अभिभाषण प्रस्तावित है और मुख्यमंत्री स्वयं वित्त मंत्री भी हैं। ऐसे में बजट पर विस्तृत चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि बजट पर कम से कम चार दिन और विभागवार चर्चा के लिए भी चार दिन निर्धारित किए जाएं। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सरकार सत्र की अवधि को सीमित कर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। उन्होंने बजट सत्र को कम से कम 21 दिन तक आयोजित करने की मांग रखी। उनके अनुसार, लोकतंत्र में सदन ही वह मंच है जहां जनता से जुड़े सवालों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। यशपाल आर्य ने स्पष्ट किया कि इस बार विपक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में उठाने की तैयारी में है। इनमें विद्यालय विहीन शिक्षकों की नियुक्ति, विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, आपदा प्रभावितों को राहत वितरण की स्थिति, राज्य में ठप पड़े विकास कार्य, किसान आत्महत्या के मामले, किसानों को फसल का उचित मूल्य न मिलना, महिलाओं पर बढ़ते उत्पीड़न की घटनाएं, कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों और दलितों पर अत्याचार तथा बिगड़ती कानून-व्यवस्था जैसे विषय शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन सवालों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पास ठोस जवाब नहीं हैं। विपक्ष का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही सर्वोपरि है और यदि सत्र की अवधि कम रखी जाती है तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत होगा।

अब सभी की बजट सत्र पर है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार विपक्ष की मांगों पर क्या रुख अपनाती है और सदन के भीतर बहस का स्वरूप कैसा रहता है। फिलहाल, बजट सत्र से पहले ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है और आने वाले दिनों में यह टकराव और भी बढ़ सकता है।

रायपुर से भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ भी विवादों में घिरे

जहां एक ओर प्रणव चौंपियन और हरक सिंह रावत के आरोपों ने राजनीतिक माहौल को गरमाया, वहीं देहरादून के रायपुर से भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ भी पिछले दिनों में विवादों में घिर गए। शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में कथित मारपीट और गाली-गलौज की घटना को लेकर विपक्ष ने उन्हें आड़े हाथों लिया। विपक्षी दलों ने इसे सत्ता के दुरुपयोग और अनुशासनहीन आचरण का उदाहरण बताते हुए कड़ी आलोचना की। हालांकि, बाद में उमेश शर्मा काऊ ने प्रेस वार्ता कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा कि घटना को लेकर यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो उन्हें खेद है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था। लेकिन राजनीतिक माहौल में यह मुद्दा भी चर्चा का विषय बन गया और विपक्ष ने इसे सरकार की छवि से जोड़कर पेश किया। लगातार बढ़ते इन विवादों ने प्रदेश की राजनीतिक गरिमा पर प्रश्न खड़े किए हैं। उत्तराखंड की राजनीति को अपेक्षाकृत शालीन और संतुलित माना जाता रहा है, लेकिन हालिया घटनाओं ने इस धारणा को चुनौती दी है। राजनीतिक दलों के बीच संवाद की जगह सार्वजनिक आरोपों ने ले ली है। चुनावी वर्ष में इस तरह के विवाद असामान्य नहीं होते, लेकिन जब व्यक्तिगत आरोप और पुराने वीडियो मुख्य मुद्दा बन जाएं तो विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी प्रश्न पीछे छूट जाते हैं। यही चिंता राज्य के बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों के बीच भी दिखाई दे रही है। 9 मार्च से शुरू होने वाला बजट सत्र बढ़ते तनाव की अग्निपरीक्षा साबित हो सकता है। विपक्ष जहां सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है, वहीं सत्ता पक्ष भी अपनी उपलब्धियों को सामने रखने की रणनीति बना रहा है। ऐसे में सदन के भीतर तीखी नोकझोंक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इन सबके बीच होली का त्योहार दस्तक दे रहा है रंगों, मेल-मिलाप और आपसी सौहार्द्र का प्रतीक बनकर। उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं में होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि मनमुटाव मिटाने और रिश्तों को नया आयाम देने का अवसर भी रही है।अब बड़ा प्रश्न यही है कि क्या होली का यह पर्व राजनीतिक तल्खियों को कुछ हद तक कम कर पाएगा? क्या विरोधी खेमों के नेता त्योहार के अवसर पर संवाद और सौहार्द का संदेश देंगे? या फिर चुनावी गणित और रणनीतियां त्योहार की मिठास पर भारी पड़ेंगी?

प्रदेश की जनता चाहती है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह रहें, लेकिन व्यक्तिगत कटुता और आरोपों की तीव्रता कम हो। क्योंकि अंततः सियासत का असर आम लोगों के सामाजिक संबंधों पर भी पड़ता है। जब नेता एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हैं तो समाज में भी विभाजन की रेखाएं गहरी होती हैं। उत्तराखंड की पहचान शांति, सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि से जुड़ी रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक दल संवाद की राह अपनाएंगे और विकास व जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। होली का त्योहार यदि इस दिशा में एक प्रतीकात्मक शुरुआत भी कर दे, तो यह प्रदेश की लोकतांत्रिक परंपरा के लिए सकारात्मक संकेत होगा। फिलहाल, चुनावी आहट, बजट सत्र की तैयारी और लगातार जारी आरोप-प्रत्यारोप के बीच उत्तराखंड की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। आने वाले दिन तय करेंगे कि सियासी तापमान और बढ़ेगा या फिर रंगों का यह पर्व कुछ ठंडक लेकर आएगा।

विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट सत्र

उत्तराखंड में 9 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसे चुनाव से पहले का अंतिम पूर्ण बजट सत्र माना जा रहा है। ऐसे में इस सत्र की राजनीतिक और प्रशासनिक अहमियत और बढ़ गई है। सरकार जहां अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को सामने रखने और आगामी वर्ष की योजनाओं का खाका पेश करने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष भी विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार इस बजट को विकास उन्मुख और जनहितकारी बताने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, बजट में बुनियादी ढांचे, सड़क और सेतु निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, शिक्षा, पर्यटन और स्वरोजगार योजनाओं पर विशेष जोर दिया जा सकता है। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं के विस्तार की भी संभावना है।

वित्त विभाग द्वारा अंतिम रूप दिए जा रहे इस बजट में ग्रामीण विकास, पेयजल, कृषि और आपदा प्रबंधन के लिए भी अतिरिक्त प्रावधान किए जाने की चर्चा है। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा संवेदनशीलता को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज या नई पहल की घोषणा भी संभव मानी जा रही है। दूसरी ओर विपक्ष पहले ही संकेत दे चुका है कि वह बेरोजगारी, महंगाई, कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और हालिया विवादों जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने कई घोषणाएं कीं, लेकिन जमीनी स्तर पर अपेक्षित परिणाम नहीं दिखे। ऐसे में सदन के भीतर तीखी बहस और टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चुनावी वर्ष से पहले पेश किया जाने वाला यह बजट केवल वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि सरकार की राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं का संकेत भी होगा। सरकार के लिए यह अवसर है कि वह अपने विकास एजेंडे को मजबूती से प्रस्तुत करे, जबकि विपक्ष के लिए यह मंच है कि वह जनहित से जुड़े सवालों को प्रभावी ढंग से उठाए।

सुरक्षा और व्यवस्थागत तैयारियों को लेकर भी प्रशासन सतर्क है। सत्र के दौरान विधानसभा परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। साथ ही संभावित प्रदर्शन और विरोध कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में हैं। यह बजट सत्र उत्तराखंड की राजनीति के लिए अहम पड़ाव साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में सदन की कार्यवाही और पेश होने वाले प्रावधान तय करेंगे कि चुनावी वर्ष से पहले सरकार जनता को किस तरह का संदेश देना चाहती है और विपक्ष किस रणनीति के साथ मुकाबला करेगा।

सुरक्षित और स्मार्ट होगी चारधाम यात्रा

आस्था, विश्वास और हिमालय की दिव्य वादियों में बसने वाले भगवान केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन की पवित्र कामना हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की ओर खींच लाती है। चारधाम यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की गहरी भावनाओं, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। इसी आस्था को सहज, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए इस बार राज्य सरकार ने समय रहते व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। शुक्रवार को मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य, सुरक्षा, ट्रैफिक, बिजली, साफ-सफाई और तकनीकी व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत मंथन किया गया। खास तौर पर केदारनाथ-बद्रीनाथ मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरी तरह क्रियाशील रखने, ऊंचाई पर यात्रियों के लिए चिकित्सा सहायता मजबूत करने और आपात स्थितियों से निपटने के निर्देश दिए गए हैं।

इस बार यात्रा को "स्मार्ट" बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। प्रमुख पड़ावों पर क्यूआर कोड, स्पष्ट साइनेज, व्हाट्सएप अलर्ट सिस्टम, ट्रैफिक मॉनिटरिंग और मानक संचालन प्रक्रिया लागू की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को हर कदम पर जानकारी और सुरक्षा मिल सके। आपदा या खराब मौसम की स्थिति में त्वरित निर्णय के लिए जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं और आवश्यक मशीनरी व संसाधन पहले से तैनात रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट

हिमालय की गोद में बसे भगवान के पवित्र धामों की ओर बढ़ते कदम केवल एक यात्रा नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था विश्वास और आत्मिक शक्ति का प्रतीक होते हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा सदियों से भारतीय सनातन परंपरा का जीवंत केंद्र रही है। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच गूंजते हर हर महादेव और जय बद्री विशाल के जयकारे केवल धार्मिक उत्साह नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं। हर वर्ष देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु कठिन रास्तों और प्रतिकूल मौसम के बावजूद इस पवित्र यात्रा पर निकलते हैं। इसी आस्था को सुरक्षित और सुगम बनाने के संकल्प के साथ धामी सरकार ने इस बार चारधाम यात्रा 2026 को लेकर समय रहते व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं को किसी भी स्तर पर असुविधा न हो और यात्रा अनुभव पहले से अधिक सुरक्षित व्यवस्थित और तकनीकी रूप से सक्षम बने। शुक्रवार को मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा 2026 को लेकर एक विस्तृत उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसमें दर्जनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एक छत के नीचे एकत्र हुए। बैठक में स्वास्थ्य साफ सफाई बिजली आपूर्ति ट्रैफिक प्रबंधन आपदा नियंत्रण और तकनीकी नवाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन मंथन किया गया। सरकार का जोर इस बात पर रहा कि यात्रा मार्ग पर हर व्यवस्था समय से पहले पूरी तरह तैयार हो और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए समुचित संसाधन उपलब्ध रहें। चारधाम यात्रा में विशेषकर केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति लंबे समय से चिंता का विषय रही है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी ठंड और थकान के कारण हृदय रोगियों बुजुर्गों और अन्य रोगियों की तबीयत बिगड़ने की घटनाएं सामने आती रही हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे को स्पष्ट निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग के सभी चिकित्सालय यात्रा आरंभ होने से पहले पूरी तरह क्रियाशील स्थिति में हों। आवश्यक दवाइयों ऑक्सीजन सिलेंडर एंबुलेंस और प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। जहां जरूरत हो वहां अस्थायी चिकित्सा इकाइयां स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य के साथ साथ बिजली आपूर्ति को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग पर निर्बाध और संतुलित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी पड़ाव या धाम में अंधकार या तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो। बिजली व्यवस्था मजबूत रहने से अस्पताल संचार प्रणाली और अन्य आवश्यक सेवाएं सुचारु रूप से संचालित हो सकेंगी। चारधाम यात्रा के दौरान ट्रैफिक जाम एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आता है। देशभर से लाखों श्रद्धालु सीमित समय में उत्तराखंड पहुंचते हैं जिससे कई स्थानों पर लंबा जाम लग जाता

है। इस बार ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर विशेष रणनीति तैयार की गई है। आपदा प्रबंधन और पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी जाम भीड़ या आपात स्थिति उत्पन्न हो वहां यात्रियों को तुरंत व्हाट्सएप अलर्ट के माध्यम से सूचना दी जाए। इससे श्रद्धालु वैकल्पिक मार्ग अपना सकेंगे और अनावश्यक भीड़ से बचाव संभव होगा। यदि खराब मौसम भूस्खलन या किसी दुर्घटना के कारण यात्रा रोकने की आवश्यकता पड़े तो इसका निर्णय कब और कहां लिया जाएगा इसकी जिम्मेदारी आयुक्त गढ़वाल मंडल को सौंपी गई है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि निर्णय में विलंब न हो और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि बनी रहे। यात्रा मार्ग पर मशीनें जेसीबी उपकरण और अन्य आवश्यक संसाधन पहले से तैनात रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके। यात्रा के दौरान पशुओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है विशेषकर केदारनाथ मार्ग पर खच्चर और घोड़े बड़ी संख्या में उपयोग किए जाते हैं। सरकार ने पशुओं के पंजीकरण उपचार और किसी अनहोनी की स्थिति में उचित प्रबंधन के स्पष्ट निर्देश दिए हैं ताकि पशु और यात्री दोनों सुरक्षित रहें। तकनीक के मोर्चे पर इस बार एक नई पहल देखने को मिलेगी। प्रमुख धार्मिक स्थलों और महत्वपूर्ण पड़ावों पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। श्रद्धालु इन कोड को स्कैन करके उस स्थान का इतिहास मार्गदर्शन आवश्यक सुविधाओं और आपात संपर्क की जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त पूरे मार्ग पर स्पष्ट और बड़े साइनेज लगाए जाएंगे ताकि पहली बार आने वाले यात्री भी रास्ता न भटकें। चारधाम यात्रा संचालन के लिए एक मानक प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की जाएगी जिसमें सभी विभागों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से निर्धारित होंगी। इससे समन्वय बेहतर होगा और कार्यों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित होगी। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु अपर पुलिस महानिदेशक डॉ वी मुरुगेशन आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडेय सहित स्वास्थ्य पुलिस लोक निर्माण पेयजल परिवहन पर्यटन विद्युत और आईटीडीए समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी विभागों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि चारधाम यात्रा राज्य की पहचान और श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय है इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। धामी सरकार की यह व्यापक तैयारी संकेत देती है कि इस बार चारधाम यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सुशासन और समन्वित प्रबंधन का उदाहरण बनने जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में दिव्य धामों के दर्शन कर सकें और उत्तराखंड की छवि एक जिम्मेदार और सक्षम तीर्थ राज्य के रूप में और मजबूत हो।

चारधाम यात्रा में बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति की डिजिटल पहल

विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और श्रद्धालु-अनुकूल बनाने की दिशा में श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने इस वर्ष एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल की है। यात्रा के बढ़ते दायरे और लाखों श्रद्धालुओं की भागीदारी को देखते हुए समिति ने मंदिर व्यवस्थाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का निर्णय लिया है, ताकि दर्शन व्यवस्था, सूचना प्रणाली और सेवा प्रबंधन पहले से अधिक सरल और प्रभावी बन सके। समिति का उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं को लंबी प्रतीक्षा, अव्यवस्था या जानकारी के अभाव जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दर्शन से जुड़ी सूचनाएं, महत्वपूर्ण अपडेट और मंदिर सेवाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराई जाएगी। इससे यात्रा प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी और श्रद्धालुओं का अनुभव अधिक सहज होगा। यह कदम न केवल प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करेगा बल्कि चारधाम यात्रा को पारंपरिक आस्था और आधुनिक तकनीक के समन्वय का उदाहरण भी बनाएगा। समिति का मानना है कि तकनीक के इस समावेश से यात्रा का संचालन अधिक व्यवस्थित होगा और श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित, सरल और संतोषजनक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव लोक निर्माण ने किया चारधाम यात्रा मार्गो का स्थलीय निरीक्षण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर शुक्रवार को सचिव लोक निर्माण डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने आगामी चारधाम यात्रा के दृष्टिगत उत्तरकाशी-भटवाड़ी -हर्षिल-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-34 में निर्माणाधीन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय द्वारा बी.आर.ओ के अधिकारियों को आगामी चारधाम यात्रा से पूर्व 15 अप्रैल, 2026 तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-34 को दुरूस्त किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को यात्रा मार्ग से मलवा हटाने एवं सभी डेंजर/लैंडस्लाइड जोन में आवश्यकतानुसार कटिंग करते हुए चौडाई बढ़ाने तथा हॉट मिक्स करने के निर्देश दिए। सचिव लोक निर्माण ने अधिकारियों को स्वाडी-गाड में निमाण ाधीन 85 मी० स्पान स्टील सेतु के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा यात्रा शुरू होने से पूर्व स्टील गर्डर सेतु का लॉचिंग, डैक स्लैब का कार्य एवं एप्रोच रोड का भी निर्माण कार्य पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर राज्य सरकार का संकल्प है कि चार धाम से संबंधित सभी कार्य तीव्र गति एवं प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएं। सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने मुखवा से धराली तक पैदल मार्ग एवं पैदल सेतु का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में दौरान उन्होंने धराली क्षेत्र में घटित भीषण दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त धराली स्थित पैदल सेतु के मरम्मत का कार्य प्रारम्भ न होने एवं धराली एवं हर्षिल के बीच दो स्थानों पर क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य प्रारम्भ न होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को तय समय के अंदर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा तय समय पर निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बी.आर.ओ एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया गया कि आगामी चार धाम यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व ही राष्ट्रीय राजमार्ग के सम्बन्धित स्थलों पर हॉट मिक्स का कार्य करवाते हुए राइडिंग क्वालिटी मे सुधार सुनिश्चित किया जायेगा। इस अवसर पर इं० रणजीत सिंह, इं० विजय कुमार, इं० नवीन लाल, इं० कैलाश चन्द्र नौटियाल, मेजर सन्तोष कुमार, एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

होली पर्वः रंगों एवं सामाजिक व्यवहार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

रुचि सिंह

भारत एक त्योहारों वाला देश है। यहाँ अलग अलग राज्यों के अलग-अलग त्योहार मनाए जाते हैं और, उनके अपने सामाजिक आस्था और वैज्ञानिक महत्व होते हैं। परंतु कुछ त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास पूर्वक मनाए जाते हैं और उन्हीं कुछ पर्वों में एक होली है जो पूरे देश में बड़े धूम-धाम से मनाया जाता है।

होली की बात करे तो यह रंगों उल्लास एवं सामाजिक मिलन वाला त्योहार है। इसे अलग मनोविज्ञान के रूप में देखें तो यह एक तनाव, चिंता, अवसाद को कम करने का अचूक त्योहार है। होली एक मनोवैज्ञानिक उत्सव है (मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मनुष्य का अनुभव और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और यह बड़े ही सामाजिक रूप से समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है जो मानव प्रकृति के विभिन्न पक्षों का शोधमूलक अध्ययन करता है) होली एक ऐसा उत्सव है जो, सामाजिक दूरियों को मिटाकर मानसिक तनाव को कम करता है। सकारात्मकता लाता है। यह रंगों के माध्यम से खुशी सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देता है, जिससे मन के विकार और उदासी दूर होते हैं।

कैडबम्स अस्पताल की वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक ने भी माना है कि ''रंगों का हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो हमारी भावनाओं और ऊर्जा के स्तर को सूक्ष्म रूप से आकार देते हैं'' उदाहरण के लिए लाल, नारंगी और पीले जैसे चमकीले रंग आमतौर पर ऊर्जा, जोश और गर्माहट से जुड़े होते हैं जो अक्सर उत्साह पैदा करते हैं। इस के विपरीत नीला और हरा रंग शांति और आराम को बढ़ावा देते हैं। चमकीले जीवंत रंगों के संपर्क में आने से मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शोध से पता चलता है कि ऐसे रंग डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर स्त्राव को बढाकर तनाव कम करने और मनोदशा में सुधार लाने में मदद कर सकते हैं। रंगों की बौछार के बीच सामूहिक रूप से मिलकर जश्न मनाने से समुदाय और अपनेपन की भावना को बढ़ावा मिलता है, जो मानसिक दृढ़ता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। विकृति और बुराई जब मन में पनपते हैं तो उसे नष्ट करना आवश्यक होता है। जो लोग अपनी बुराई को आत्मिक संस्कार शक्ति से नष्ट नहीं कर पाते हैं उनके द्वारा समाज पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को सामुहिक रूप से नष्ट करने का प्रतीक ही होलिका दहन है। होलिका दहन की कथा के अनुसार अग्नि सुरक्षा कवच से भी होलिका बच नहीं पाई क्योंकि वो सत्य के विरुद्ध पाप वृत्ति अनाचार भ्रष्टाचार से घिरी थी। होलिका दहन सांकेतिक रूप से इस तथ्य का भी सूचक है कि भ्रष्ट पथ गामियों की पराजय सुनिश्चित है। मनोवैज्ञानिक पहलू को देखें तो, होलिका दहन ध्वसात्मक और नकारात्मक वृत्तियों की हार और सत्य और सृजनात्मक वृत्ति के विजय का प्रतीक भी है।

होली एक उमंग वाला त्योहार है इसमें कुछ विशेष उत्साहित लोग हुड़दंग और फूहड़ता का प्रदर्शन भी करते हैं। कालान्तर में लोग कीचड़ पानी और रंग से खेलते थे और अगर इसे अत्यंत सकारात्मकता के दृष्टिकोण से विश्लेषण करें तो मनुष्य मनोविज्ञान के तहत अपने अंदर के कीचड़ रूपी घृणा को बाहर निकाल कर अपने और समाज का कल्याण करने की कोशिश कर रहे होते थे, परंतु इस फुहड़ता और हुड़दंग में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सीमा को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। होली खेलते समय जो भी मनुष्य अन्दर से बैर से भरा होता है, वो यह सीमा रेखा को पहचान नहीं पाता है। और गलत हरकत कर बैठता है। मनुष्य बहुत से ऐसा काम करना चाहता है जो नियम के विरुद्ध होते हैं, वह समाज के नियम से बंधा होता है और यह नियम होली के अवसर पर वह तोड़ना चाहता है परन्तु यह नियम को तोड़ते समय उसे पूरी सावधानी रखनी

चाहिए।

ओशो ने भी होली के लिए कहा है ''होली का मतलब है खुलकर जीन, नाचना, गाना और जीवन के हर रंग में रम जाना''। रंगों के साथ मन के साथ मन के विकारों को बाहर फेकने का अध्यात्मिक पर्व होली है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह बात बहुत मायने रखती है कि हम अपने मन की बात किसी न किसी रूप में व्यक्त करे। हिंदू पर्व होली उसकी सामूहिक माध्यम है। रंगों का भी अपना मनोविज्ञान होता है जिसे रंग मनोविज्ञान भी माना जाता है। विभिन्न रंगों के मानव मनोदशा और व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है, रंगों को ऐतिहासिक रूप से मानव मनोवैज्ञानिक लक्षणों और व्यक्तित्व प्रकारों से भी जोड़ा गया है।

20वीं शताब्दी के मनोचिकित्सक और मनोविश्लेषक कार्ल जंग ने कहा है कि ''रंग अवचेतन मन की मातृभाषा है और रंग मनुष्य के मुख्य मानसिक कार्यों को व्यक्त करते हैं'' रंगों के साथ हर वयक्ति का व्यक्तिगत जुड़ाव होता है। मनोचिकित्सक का मानना है कि ''रंग लोगों के लिए उनके व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर अर्थ रखते हैं। यह परवरिश, शुरुआती अनुभव हो सकता है। इस लिए प्रत्येक व्यक्ति का अलग-अलग पसंदीदा रंग होता है। किसी के लिए चटक रंग आराम का होता है तो किसी के लिए ये गुस्सा का भी हो सकता है। यह रंगों का खेल प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पसंद पर निर्भर करता है। होली का त्यौहार केवल रंगों से उत्सव मनाने का नाम नहीं है बल्कि व्यक्तिगत विकास और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीकृत करने का मौका है।

इस होली जम कर रंग से खेलें परंतु सामाजिक मर्यादाओं की सीमाओं को और सामाजिक पारिवारिक रिश्तों की मर्यादाओं को प्राथमिकता देना ना भूलें। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी सीमा पहचानता है तो आधे से ज्यादा दु:ख, उदासी खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। होली नवीनीकरण, विकास और जीवन एवं खुशहाली का उत्सव है। रंगों के महत्व को समझने के लिए प्रकृति को करीब से निहारिए, आप को खुद ब खुद अहसास हो जाएगा कि रंग हमारे तन व मन में नई ऊर्जा, उमंग और उत्साह का संचार करतें हैं।

(रुचि सिंह मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर हैं एवं सामाजिक मनोविज्ञान के विभिन्न आयामों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करती हैं)।

शिक्षा की किताब में अदालत पर सवाल

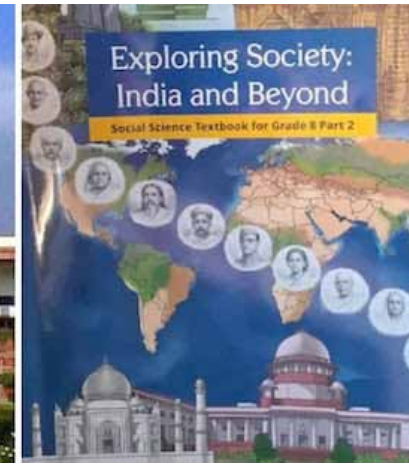

देश की सर्वोच्च अदालत की भूमिका और अधिकारों को लेकर एनसीईआरटी की एक पाठ्यपुस्तक में किए गए उल्लेखों पर विवाद गहराने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गंभीर आपत्ति जताई है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शैक्षणिक पुस्तकों में संवैधानिक संस्थाओं का चित्रण संतुलित, तथ्यात्मक और जिम्मेदार होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में टिप्पणी की कि आलोचनात्मक अध्ययन और संस्थागत गरिमा के बीच एक रेखा होती है, जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और छात्रों के सामने उसकी भूमिका को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे संविधान के प्रति विश्वास और समझ मजबूत हो, न कि भ्रम की स्थिति पैदा हो। अदालत ने संबंधित प्राधिकरण से स्पष्टीकरण मांगते हुए संकेत दिया कि यदि सामग्री तथ्यों के अनुरूप नहीं पाई गई तो आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट।

देश की न्याय व्यवस्था को लेकर उठे एक बड़े विवाद ने शिक्षा जगत और न्यायपालिका दोनों को एक साथ चर्चा के केंद्र में ला दिया है। कक्षा आठवीं की सामाजिक विज्ञान की एक पाठयपुस्तक में न्यायपालिका से जुड़े उल्लेखों को लेकर मचे विवाद पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया है कि संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। 26 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित कक्षा आठवीं की सामाजिक विज्ञान भाग-2 की पुस्तक के एक अध्याय पर गंभीर आपत्ति जताई। सुनवाई की अध्यक्षता करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि विद्यालयी शिक्षा में दी जाने वाली सामग्री संतुलित, तथ्याधारित और जिम्मेदार होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि बच्चों के मन में किसी भी संवैधानिक संस्था के प्रति एकतरफा धारणा बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल नहीं है। दरअसल, 'एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड, खंड-द्वितीय' नामक पुस्तक में न्यायपालिका से जुड़े एक अध्याय में अदालतों में लंबित मामलों की संख्या और न्यायिक तंत्र में कथित भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया था। इस सामग्री को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई और मामला अंतत: सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है और उसकी आलोचना तथ्यों व संतुलन के साथ की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि स्कूली स्तर पर विद्यार्थियों को इस प्रकार की सामग्री पढ़ाई जाएगी तो उनके मन में संस्थाओं के प्रति नकारात्मक और एकपक्षीय दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। अदालत ने स्पष्ट

शब्दों में कहा कि "माफी मांग लेना पर्याप्त नहीं है, संस्थागत गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले मामलों में जिम्मेदारी तय होगी।" इस पूरे प्रकरण में एनसीईआरटी ने अदालत के समक्ष यह स्वीकार किया कि पुस्तक के संबंधित अंशों को लेकर उनसे त्रुटि हुई है। संस्था की ओर से यह भी कहा गया कि विवादित सामग्री को हटाकर संशोधित संस्करण जल्द जारी किया जाएगा। साथ ही अदालत से औपचारिक क्षमा याचना भी की गई। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि केवल संशोधन का आश्वासन पर्याप्त नहीं है। अदालत ने तत्काल प्रभाव से पुस्तक के वितरण और उपयोग पर रोक लगाने का आदेश दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि पुस्तक की सभी प्रतियां चाहे वे मुद्रित रूप में हों, डिजिटल रूप में हों या खुदरा बाजार में उपलब्ध संस्करण, तुरंत प्रभाव से वापस ली जाएं। अदालत ने डिजिटल मंचों पर उपलब्ध सामग्री को भी हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही एनसीईआरटी के निदेशक को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का पूर्ण अनुपालन किया जाए और दो सप्ताह के भीतर अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि विद्यालय परिसरों में भेजी गई प्रतियां भी तत्काल वापस ली जाएं। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह टिप्पणी भी की कि यदि इस प्रकार के मामलों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो इससे आम जनता का न्यायपालिका पर विश्वास कमजोर हो सकता है।

आखिर पुस्तक में क्या था विवादित

विवाद की जड़ उस अध्याय में निहित है जिसमें देश की न्यायिक प्रणाली की संरचना और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। पुस्तक में विभिन्न स्तरों की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या का उल्लेख किया गया था। अध्याय में यह बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 81 हजार मामले लंबित हैं, उच्च न्यायालयों में करीब 62 लाख से अधिक मामले लंबित हैं और अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 4 करोड़ 70 लाख से अधिक मामले विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त, अध्याय में न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों का उल्लेख भी किया गया था। पुस्तक में एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के कथन का हवाला देते हुए कहा गया था कि न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार की घटनाएं जनता के विश्वास को प्रभावित करती हैं। यही उल्लेख विवाद का प्रमुख कारण बना। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इस प्रकार की प्रस्तुति विद्यार्थियों के सामने न्यायपालिका की एकतरफा और नकारात्मक छवि प्रस्तुत करती है। उनका कहना था कि न्यायिक सुधारों, पारदर्शिता के प्रयासों और संस्थागत मजबूती के पहलुओं को समान महत्व नहीं दिया गया, जिससे अध्याय संतुलित नहीं रह गया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी सुनवाई के दौरान यही सवाल उठाया कि क्या पाठ्यपुस्तक में संस्थागत सुधारों, न्यायिक जवाबदेही की व्यवस्थाओं और न्यायपालिका की सकारात्मक भूमिका का भी समुचित उल्लेख किया गया है। अदालत ने कहा कि आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन वह तथ्यों और संतुलन पर आधारित होनी चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में संविधान, न्याय और संस्थाओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित की जानी चाहिए। यदि सामग्री केवल समस्याओं को रेखांकित करती है और समाधान या व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत नहीं करती, तो वह अधूरी और भ्रामक हो सकती है। इस मामले ने शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम निर्माण और संस्थागत जवाबदेही पर व्यापक बहस को जन्म दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाठ्यपुस्तकों में समसामयिक मुद्दों का समावेश आवश्यक है, लेकिन उनकी भाषा, संदर्भ और प्रस्तुति अत्यंत संतुलित होनी चाहिए। अब सभी की नजर 11 मार्च 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां यह स्पष्ट होगा कि अदालत इस मामले में आगे क्या रुख अपनाती है। फिलहाल, सर्वोच्च न्यायालय के कड़े आदेश ने यह संदेश दे दिया है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा सर्वोपरि है और शिक्षा के माध्यम से उनके प्रति संतुलित दृष्टिकोण विकसित करना ही समय की मांग है।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बिल्डिंग बायलॉज संशोधन को लेकर समिति गठित की

उत्तराखण्ड राज्य की बढ़ती भूकंपीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने भवन निर्माण नियमों को अधिक सुरक्षित और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। भारतीय मानक ISO 1893-2025 के अनुसार पूरे राज्य के भूकंप जोन छह में शामिल होने के बाद अब बिल्डिंग बायलॉज में व्यापक संशोधन किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन द्वारा वर्तमान बिल्डिंग बायलॉज की समीक्षा एवं संशोधन हेतु सीएसआईआर-सीबीआरआई रुड़की के निदेशक प्रो. आर. प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। यूएलएमएमसी के निदेशक डॉ. शांतनु सरकार को समिति का संयोजक बनाया गया है। बता दें कि वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में बिल्डिंग बायलॉज भारतीय मानक ब्यूरो के पुराने संस्करण ISO 1893-2002 पर आधारित हैं।

समिति में सीबीआरआई रुड़की, भारतीय मानक ब्यूरो, आईआईटी, ब्रिडकुल, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, विकास प्राधिकरणों तथा भू-वैज्ञानिक विशेषज्ञों सहित विभिन्न तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। समिति वास्तुविदों के साथ ही विभिन्न अभियंताओं से भी विचार-विमर्श करेगी। समिति का उद्देश्य राज्य के मौजूदा बायलॉज का गहन अध्ययन करते हुए उन्हें वर्तमान भूकंपीय मानकों, जलवायु परिस्थितियों और आधुनिक निर्माण तकनीकों के अनुरूप तैयार करना है। मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों और बढ़ती भूकंपीय संवेदनशीलता को देखते हुए भवन निर्माण के नियमों में परिवर्तन किया जा रहा है। राज्य सरकार भवन बायलॉज को अधिक प्रभावी, व्यावहारिक और आपदा-सुरक्षित बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

समिति भवन बायलॉज को अधिक व्यवहारिक, सुरक्षित और आपदा-रोधी बनाने के लिए अपने सुझाव देगी। उन्होंने कहा कि संशोधित नियमों से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और आपदा जोखिम में कमी आएगी। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल नियमों में बदलाव करना नहीं बल्कि सुरक्षित निर्माण की संस्कृति विकसित करना है। उन्होंने बताया कि संशोधित बिल्डिंग बायलॉज में भूकंप-रोधी डिजाइन, भू-तकनीकी जांच, विंड लोड और स्ट्रक्चरल सेफ्टी से जुड़े प्रावधानों को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

साथ ही स्थानीय पारंपरिक निर्माण तकनीकों और जलवायु अनुकूल विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे सतत एवं आपदा-सक्षम विकास सुनिश्चित हो सके। बता दें कि नए बिल्डिंग बायलॉज लागू होने से भवनों की संरचनात्मक मजबूती बढ़ेगी, आपदा के दौरान जन-धन की हानि कम होगी और सुरक्षित व टिकाऊ शहरी विकास व निर्माण को नई दिशा मिलेगी। समिति अपनी रिपोर्ट उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा आवास विभाग को सौंपेगी।

समिति द्वारा तैयार की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर आवास विभाग द्वारा बायलॉज में आवश्यक संशोधन एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

समिति का कार्यक्षेत्र

- उत्तराखण्ड राज्य के वर्तमान बिल्डिंग बायलॉज की विस्तृत समीक्षा, विश्लेषण एवं मौजूदा तकनीकों का आकलन।
- राज्य में मौजूद भूकंप, भूस्खलन और अन्य आपदा जोखिमों को समाहित करते हुए संशोधित बिल्डिंग बायलॉज का मसौदा तैयार करना।
- भूकंप-रोधी डिजाइन, नई निर्माण तकनीकों एवं संरचनात्मक सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को शामिल करना।
- पारंपरिक पहाड़ी निर्माण प्रणालियों को वैज्ञानिक रूप से आधुनिक नियमों में समाहित करना।
- पर्यावरण संरक्षण और जलवायु अनुकूल निर्माण के लिए विशेष प्रावधान तैयार करना।
- संशोधित नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना एवं दिशा-निर्देश प्रस्तुत करना।
- इंजीनियरों, योजनाकारों एवं संबंधित विभागों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के सुझाव देना।

समिति में ये हैं शामिल

समिति की अध्यक्षता सीएसआईआर-सीबीआरआई, रुड़की के निदेशक प्रो. आर. प्रदीप कुमार करेंगे, जबकि यूएलएमएमसी, देहरादून के निदेशक डॉ. शांतनु सरकार को संयोजक बनाया गया है।

समिति में डॉ. अजय चौरसिया (मुख्य वैज्ञानिक, सीबीआरआई रुड़की), प्रो. महुआ मुखर्जी (वास्तुकला विभाग, आईआईटी रुड़की), सुश्री मधुरिमा माधव (वैज्ञानिक 'C', भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली), डॉ. पी.के. दास (वरिष्ठ ग्रामीण आवास सलाहकार, यूएनडीपी), आर्किटेक्ट एस. के. नेगी (पूर्व मुख्य वैज्ञानिक, सीबीआरआई शिमला), उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के नामित प्रतिनिधि, ब्रिडकुल के प्रबंध निदेशक, लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, राज्य के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रतिनिधि, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण और हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के साथ-साथ भूकंप विशेषज्ञ धर्मेन्द्र कुशवाहा एवं भू-भौतिक विज्ञानी डॉ. विशाल वत्स सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं।

उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा टौंस-यमुना घाटी के ऐतिहासिक लोक पर्व का भव्य आयोजन

उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा आज उत्तराखंड के लोकप्रिय टौंस एवं यमुना घाटी के ऐतिहासिक एवं पारंपरिक लोक पर्व का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यमुना घाटी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं, वेशभूषा, रीति-रिवाजों और लोकगीतों की विशेष प्रस्तुति दी गई। इससे जनसमूह को क्षेत्र की गौरवशाली परंपरा से रूबरू होने का अवसर मिला। हिमालयी अंचल की सुदूरवर्ती टौंस एवं यमुना घाटी की समृद्ध लोक परंपराओं को सहेजते हुए बुधवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून के तत्वावधान में ऐतिहासिक एवं पारंपरिक लोक पर्व 'मरोज' का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों द्व ारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम का संचालन प्रेस क्लब के महामंत्री योगेश सेमवाल एवं लोक कलाकार व लोक विधाओं के पुरोधा नंदलाल भारती ने संयुक्त रूप से किया।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

संस्कृति विभाग के सांस्कृतिक दल द्वारा एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई, जिनमें टौंस और यमुना घाटी की पारंपरिक झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दी। लोक नृत्य और लोक गीतों ने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया और पूरे सभागार में पर्व जैसा उत्साह व्याप्त रहा।

लोक पर्व 'मरोज' के महत्व पर विचार

मुख्य अतिथि विधायक मुन्ना सिंह चौहान सहित अन्य अतिथियों ने अपने संबोधन में माघ मरोज पर्व की ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे आयोजन हमारी लोक परंपराओं को जीवंत रखने का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि हिमालयी अंचल की संस्कृति हमारी पहचान है, जिसे संरक्षित और संवर्धित करना हम सभी का दायित्व है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुन्ना सिंह चौहान, विधायक विकासनगर ने कहा कि आज उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा टौंस एवं यमुना घाटी के ऐतिहासिक और पारंपरिक लोक पर्व का आयोजन वास्तव में सराहनीय और प्रेरणादायक पहल है। उन्होंने कहा कि यह गरिमामय आयोजन हमारी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूण र्ा प्रयास है।

उन्होंने कहा कि टौंस और यमुना घाटी केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं हैं, बल्कि वे हमारी पहचान, हमारी आस्था और हमारी सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं। यहां की लोक परंपराएं, वेशभूषा, रीति-रिवाज, मेले और त्योहार हमारी विरासत की अमूल्य धरोहर हैं और इन्हें संजोकर रखना हम सबका दायित्व है।

उन्होंने कहा कि आज जब आधुनिकता और पाश्चात्य प्रभाव के कारण युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से दूर होती जा रही है, ऐसे में इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन उन्हें अपनी मिट्टी, अपनी बोली और अपनी परंपराओं से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनते हैं। हमारी लोकसंस्कृति में निहित सादगी, सामूहिकता और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना हमें विशिष्ट पहचान प्रदान करती है।

उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल समाचार देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने की शक्ति भी है। उत्तरांचल प्रेस क्लब ने सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि मीडिया समाज की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अति विशिष्ट अतिथि विधायक राजपुर खजान दास ने अपने संबोधन में कहा कि 'मरोज' जैसे लोक पर्व हमारी सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं। उत्तराखंड विशेषकर जौनसार-बावर, टौंस और यमुना घाटी क्षेत्र में यह पर्व परंपरागत रूप से आपसी मेल-मिलाप और भाईचारे के साथ मनाया जाता है।

उन्होंने कहा कि गांवों में लोग घर-घर जाकर एक-दूसरे को बधाई देते हैं, जिससे सामाजिक संबंध और अधिक मजबूत होते हैं। यह पर्व केवल उत्सव नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं और सामूहिक जीवन मूल्यों को जीवित रखने का माध्यम है।

उन्होंने उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा ऐसे सांस्कृतिक आयोजन के लिए सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का महत्वपूण र्ा कार्य कर रहे हैं।

प्रेस क्लब अध्यक्ष अजय राणा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तरांचल प्रेस क्लब सदैव सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। लोक पर्वों के आयोजन का उद्देश्य अपनी परंपराओं को जीवित रखना और समाज में सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देना है।

इस अवसर पर अति विशिष्ट अतिथि पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल, विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष गीताराम गौड़, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक केएस चौहान, सीआईएमएस कॉलेज के चेयरमैन ललित जोशी के साथ ही प्रेस क्लब कोषाध्यक्ष मनीष डंगवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह नेगी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष सोबन सिंह गुसाईं, संयुक्त मंत्री मीना नेगी, शिवेश शर्मा, संप्रेक्षक विजय जोशी, कार्यकारिणी सदस्य मनमोहन लखेड़ा, मनबर सिंह रावत, हिमांशु जोशी, ओम प्रकाश जोशी, रश्मि खत्री, सुलोचना पयाल के साथ ही अनेक पत्रकार बंधु उपस्थित रहे।

भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ एवं मानव अधिकार संरक्षण केंद्र ने मनाया हर्षोल्लास के साथ होली मिलन समारोह

भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ और उत्तराखंड मानव अधिकार संरक्षण केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में प्रेस क्लब में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में श्रमजीवी पत्रकारों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम की शरूवात दिनेश चनियाल के स्वागत गीत से हुई। गायिका दुर्गा सागर और उनकी टीम ने हिंदी और गढ़वाली गीतों से कार्यक्रम में शमां बांध दिया। गायक प्रदीप के मीठे शुरों और सुरेंद्र कोहली के संगीत ने दर्शकों को होली की मस्ती का एहसास कराया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण हमारी पहचान रंग संस्था द्वारा कुमाऊँनी खड़ी होली की प्रस्तुति थी। बबीता शाह लोहानी के नेतृत्व में कुमाऊंनी होल्यारो ने उत्तराखंड की संस्कृति को इतना सजीव कर दिया कि प्रेस क्लब सभागार में उपस्थित सभी लोग अपने मोबाइल कमरों से वीडियो रील बनाने लगे। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन लखेड़ा, गिरिधर शर्मा, और प्रेम पंचोली, पुलिस अधिकारी सुरेश स्नेही, एडवोकेट गुरविंदर सिंह,ने भी अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ कुँवर राज अस्थाना ने किया। कार्यक्रम का समापन कलाकारों के सम्मान एवं भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ के केलेंडर के विमोचन के साथ संपन्न हुआ। होली मिलन समारोह 4 घंटे तक लगातार चला। कार्यक्रम कार्यक्रम में न्यायमूर्ति डॉ राजेश टंडन, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ गीता खन्ना, उच्च शिक्षा उन्नयन परिषद के अध्यक्ष डॉ देवेंद्र भसीन, सूचना विभाग के अपर निदेशक श्री आशीष त्रिपाठी, पूर्व प्रमुख मुख्य वन संरक्षक श्री जयराज, पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक वर्मा, भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक पाण्डेय, हर्षल फाउंडेशन की ट्रस्टी और प्रमुख समाजसेविका डॉ रमा गोयल, व अंतर्मन संस्था की डायरेक्टर सुषमा बच्चेती,रमानी सोशल संस्था की अध्यक्षा श्रीमती वंदना श्रीवास्तव, देवभूमि पत्रकार यूनियन के प्रदेश महामंत्री वीडी शर्मा, प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अजय राणा एवं महामंत्री श्री योगेश सेमवाल, देवभूमि टैक्स बार एसोसिएशन पदाधिकारियों के अलावा भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रवीर गायत्री ने सभी का आभार जताया होली की शुभकामनायें दी, उत्तराखंड मानव अधिकार संरक्षण केंद्र के पदाधिकारी व भारती पत्रकार संघ के राजीव थपलियाल, कुंवर राज अस्थाना, राजीव वर्मा, पीयूष अग्रवाल, पुष्कर सिंह नेगी, विजय पाल रावत नवल खाली, एसपी दुबे आशीष डोभाल रमेश नौटियाल प्रेम पंचोली सहित बड़ी संख्या में श्रमजीवी पत्रकार एवं समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

फिक्की फ्लो, एनआईएसएम एवं डीबीयूयू के संयुक्त तत्वावधान में 'इन्वेस्ट स्मार्ट, लिव बेटर' कार्यशाला का आयोजन

फिक्की लेडिज ऑरोगनीसटीऑन उत्तराखंड ने नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सेक्यूरिटीस मार्केटस तथा देव भूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के सहयोग से "इन्वेस्ट स्मार्ट, लिव बेटर" शीर्षक से एक प्रेरणादायी एवं ज्ञानवध ंक कार्यशाला का सफल आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजय कुमार द्व ारा किया गया। उन्होंने एफअलओ की चेयरपर्सन डॉ. गीता खन्ना तथा मुख्य वक्ता डॉ. सीएस पित्रेश कौशिक का स्वागत करते हुए वित्तीय साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर सीनियर वाइस चेयर ट्रिप्ती बहल, सेक्रेटरी स्मृति बट्टा, पूर्व चेयरपर्सन एवं जीबी सदस्य डॉ. नेहा शर्मा तथा सदस्य दीक्षा भाटिया की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम की डे-चेयर डॉ. नेहा चोकसी, थ्स्ब सदस्य एवं डीबीयूयू की प्रोफेसर रहीं, जिन्होंने पूरे आयोजन का कुशल संचालन किया। डीबीयूयू के विभिन्न संकायों के फैकल्टी सदस्यों एवं छात्र-प्रतिनिधियों ने वित्तीय योजना, निवेश प्रबंधन तथा संपत्ति सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा में भाग लिया। इस संयुक्त पहल ने यह स्पष्ट किया कि युवाओं को वित्तीय जागरूकता और निवेश संबंधी ज्ञान प्रदान करना आज की आवश्यकता है, जिससे वे दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त कदम बढ़ा सकें। यह कार्यशाला न केवल ज्ञानवर्धन का माध्यम बनी, बल्कि भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के प्रति जागरूकता का एक सशक्त मंच भी सिद्ध हुई।

देहरादून में विज्ञान, तकनीक और स्टार्टअप्स का संगमः यूकॉस्ट में नवाचार महोत्सव शुरू

27 फरवरी 2026 को उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (यूकॉस्ट), देहरादून स्थित आंचलिक विज्ञान केंद्र में दो-दिवसीय नवाचार महोत्सव का शुभारंभ किया गया

कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि आनंद बर्धन, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया गया। इस अवसर पर नितेश कुमार झा, सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सुराज तथा सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड सरकार, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि आनंद बर्धन ने अपने संबोधन में कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार आज के जीवन का अभिन्न अंग हैं तथा विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सोच और नवाचार की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए। नितेश कुमार झा ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं पहलुओं की जानकारी देते हुए राज्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता पर बात की। यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत ने नवाचार महोत्सव के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह आयोजन राज्य के विद्यार्थियों, स्टार्टअप्स एवं नवचारकों को अपने विचारों एवं तकनीकी उपलब्धियों के प्रदर्शन हेतु एक सशक्त मंच प्रदान करता है।

कार्यक्रम के दौरान माननीय अतिथियों ने साइंस सिटी निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण किया तथा यूकॉस्ट की विभिन्न सुविधाओं का अवलोकन किया, जिनमें सामुदायिक रेडियो स्टूडियो (विज्ञान वाणी), जैव विविधता पार्क, हाइड्रोपोनिक सेटअप, जल प्रयोगशाला, बौद्धिक सम्पदा अधिकार केन्द्र, साइंस एजुकेशन रिसर्च विंग, नालेज मैनेजमेंट सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब, हिमालयन गैलरी एवं अन्य प्रमुख अवसंरचनाएं एवं अनुभाग मुख्य रूप से शामिल रहे।

इस अवसर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार विषयक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें विभिन्न नवाचार परियोजनाओं एवं स्टार्टअप्स ने अपने उत्पाद एवं मॉडल प्रदर्शित किए। प्रथम पैनल चर्चा "विज्ञान एवं नवाचार में महिलाएं: अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा" विषय पर आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से महिला उद्यमियों ने सहभागिता की। पैनल में डॉ. रीमा पंत (शिक्षाविद्), मीनाक्षी खाती (ऐपण प्रोजेक्ट), हिमानी गोस्वामी (विकास्या), नमिता टम्टा (बाबा एग्रोटेक) शामिल रही। द्वितीय पैनल चर्चा "प्रभावी नवाचार: विज्ञान आधारित स्टार्टअप्स एवं बैंकिंग सहयोग की भूमिका" विषय पर आयोजित की गई। इस सत्र में डॉ. भुवन जोशी, डिप्टी हेड, उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी, अजय रावत (एस्ट्रोवर्स, हल्द्वानी) तथा डॉ. पीयूष गोयल, एमेरिटस वैज्ञानिक, यूकॉस्ट शामिल रहे। महोत्सव के दौरान विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे रंगोली, नाटक, प्रश्नोत्तरी, एक्सटेम्पोर, पोस्टर एवं मॉडल आदि में प्रतिभाग किया। साथ ही रचनात्मकता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स एवं स्टेम विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन भी किया गया जिससे विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। बौद्धिक संपदा अधिकार एवं करियर मार्गदर्शन विषय पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें डॉ. डी. पी. उनियाल, संयुक्त निदेशक, यूकॉस्ट द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। इस नवाचार महोत्सव में यूकॉस्ट एवं आंचलिक विज्ञान केंद्र के अधिकारियों सहित 300 से अधिक विद्यार्थियों ने सहभागिता की। विभिन्न शिक्षण संस्थानों-सार्क एजुकेशन नेपाल, हिमज्योति पब्लिक स्कूल, सेलाकुई इंटरनेशनल स्कूल, टोंस ब्रिज स्कूल, सेंट जोसेफ अकादमी, उत्तरांचल विश्वविद्यालय आदि के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।

यह नवाचार महोत्सव नीति-निर्माताओं, वैज्ञानिकों, उद्यमियों एवं विद्यार्थियों को एक साझा मंच पर लाने में प्रयासरत है तथा राज्य में नवाचार एवं वैज्ञानिक सोच को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्यरत है।

उत्तरांचल विश्वविद्यालय ने किया "उत्तराखंड शक्ति कम्युनिटी समिट" का सफल आयोजन

एसीआईसी उत्तरांचल विश्वविद्यालय फाउंडेशन, उत्तरांचल विश्वविद्यालय द्वारा 26 फरवरी 2026 को उत्तराखंड शक्ति कम्युनिटी समिट का आयोजन किया गया। इस समिट का उद्देश्य राज्यभर में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती विनोद उनियाल जी, उपाध्यक्ष- राज्य महिला उद्यमिता परिषद एवं माननीय राज्य मंत्री, उत्तराखंड सरकार ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को विशेष रूप से बढ़ाया और प्रतिभागियों को प्रेरित किया। सभा को संबोधित करते हुए श्रीमती विनोद उनियाल जी ने कहा: "महिला सशक्तिकरण प्रगतिशील उत्तराखंड की रीढ़ है। जब महिलाओं को संसाधन, प्रशिक्षण और अवसर मिलते हैं, तो वे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति बन जाती हैं।"

समिट की एक प्रमुख विशेषता रही 51 महिला उद्यमियों और परिवर्तनकर्ताओं का सम्मान, जिसे श्रीमती अनुराधा जोशी जी, उपाध्यक्ष- सुशीला देवी सेंटर फॉर प्रोफेशनल स्टडीज एंड रिसर्च द्वारा किया गया। इन महिलाओं को उद्यमिता, सामाजिक नेतृत्व और सामुदायिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समिट को कई विशिष्ट अतिथियों ने भी अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित किया। सुश्री अंकिता जोशी, उपाध्यक्ष एवं निदेशक- एसीआईसी उत्तरांचल विश्वविद्यालय फाउंडेशन ने कहा: "एसीआईसी महिलाओं को इनोवेशन, स्टार्टअप सहायता, इन्क्यूबेशन, फंडिंग और संरचित मेंटॉरशिप प्रदान करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।"

(डॉ.) धरम बुद्धि, कुलपति- उत्तरांचल विश्वविद्यालय ने कहा: "विश्वविद्यालय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहाँ महिला उद्यमियों को शोध, मार्गदर्शन और इन्क्यूबेशन समर्थन मिल सके।"

प्रो. (डॉ.) राजेश सिंह, निदेशक- अनुसंधान एवं नवाचार ने साझा किया: "महिलाओं द्वारा संचालित रिसर्च-आधारित उद्यमिता और जमीनी स्तर पर नवाचार राज्य में समावेशी विकास को तेज कर सकते हैं।"

प्रो. (डॉ.) अनीता गहलोत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी- एसीआईसी उत्तरांचल विश्वविद्यालय फाउंडेशन ने कहा: "यह समिट महिला उद्यमियों का एक मजबूत नेटवर्क बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जहाँ वे एक-दूसरे के साथ सहयोग कर सकें, अपने व्यवसायों को विस्तार दे सकें और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर सकें।"

सभी वक्ताओं ने सामूहिक रूप से महिला-नेतृत्व वाले उद्यमिता विकास, सामुदायिक भागीदारी, बाल अधिकार संरक्षण और सतत विकास के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी निकायों और उद्योग जगत के बीच सहयोग बढ़ाने तथा जमीनी स्तर पर नवाचार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उत्तराखंड शक्ति कम्युनिटी समिट एसीआईसी उत्तरांचल विश्वविद्यालय फाउंडेशन की सामाजिक सशक्तिकरण, नवाचार और समावेशी विकास के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कार्यक्रम में उद्यमियों, शिक्षाविदों, समुदाय नेताओं और छात्रों की उत्साही भागीदारी देखने को मिली, जिसने इसे संवाद, नेटवर्किंग और प्रेरणा का प्रभावशाली मंच बनाया।

अंत में, सभी विशिष्ट अतिथियों, आयोजकों और प्रतिभागियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए सत्र का सफलतापूर्वक समापन किया गया।

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि- किसी खास काम के लिए बनाई गई योजना आज आगे बढ़ सकती है। बीच में कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन उनके हल भी साथ-साथ मिलते जाएंगे। आपका सकारात्मक नजरिया आपके व्यक्तित्व को और बेहतर बनाएगा। विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखें। पति-पत्नी आपसी और पारिवारिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 1

मिथुन राशि- अपने दृढ़ निश्चय और मेहनत से आप किसी खास काम को पूरा करने में सफल रहेंगे। किसी राजनीतिक या प्रभावशाली व्यक्ति की मदद भी मिल सकती है। विद्यार्थियों और युवाओं को पढ़ाई तथा करियर से जुड़ी समस्या का हल मिलने से राहत रहेगी। युवाओं की मित्रता और गहरी हो सकती है। भाग्यशाली रंग- पीला, भाग्यशाली अंक- 2

सिंह राशि- दूसरों के मामलों में दखल न दें। स्वभाव में नरमी और ठहराव रखें। आपके अपने लोग ही काम में रुकावट डाल सकते हैं। भूमि या वाहन के लिए कर्ज लेने का सोच रहे हैं, तो अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ न लें। विद्यार्थियों को करियर की चिंता बनी रह सकती है। आयुर्वेदिक इलाज और सावधानी लाभ देगी। भाग्यशाली रंग- बादामी, भाग्यशाली अंक- 3

तुला राशि- आपकी मेहनत और प्रयास से कोई समस्या हल हो सकती है, जिससे आप अपने निजी कामों पर भी ध्यान दे पाएंगे। घर में सुधार के कुछ काम होंगे, लेकिन ध्यान रखें कि बजट से ज्यादा खर्च न हो। मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े काम अभी रोकना ठीक रहेगा। अविवाहित लोगों को अच्छी खबर मिलेगी। भाग्यशाली रंग- आसमानी, भाग्यशाली अंक- 5

धनु राशि- अतिरिक्त जिम्मेदारियों का बोझ आपको थका सकता है। किसी के साथ ज्यादा बहस में न पड़ें, वरना आपकी छवि पर असर पड़ सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं और किसी भी जोखिम वाले काम से दूर रहें। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। घर में भी शांति रहेगी। थकान बनी रह सकती है। मेडिटेशन जरूर करें। भाग्यशाली रंग- क्रीम, भाग्यशाली अंक- 6

कुंभ राशि- समय अनुकूल है। रुके हुए कामों में गति आएगी और किसी भरोसेमंद व्यक्ति पर विश्वास करना फायदेमंद साबित होगा। तनाव को खुद पर हावी न होने दें। लापरवाही से बैंक या निवेश से जुड़ा कोई काम बिगड़ सकता है। युवा मौज-मस्ती की वजह से अपने जरूरी कामों में ढिलाई कर सकते हैं। व्यायाम करें। भाग्यशाली रंग- जामुनी, भाग्यशाली अंक- 8

वृषभ राशि- स्वभाव सरल और शांत रखें। बेकार के विवाद में पड़ना आपकी छवि खराब कर सकता है। किसी भी योजना पर काम शुरू करने से पहले उस पर ठीक से सोच लें। किसी की गलत हरकत का जवाब भी शांति से दें। पति-पत्नी के बीच तालमेल की कमी से घर का माहौल बिगड़ सकता है। भाग्यशाली रंग- नीला, भाग्यशाली अंक- 7

कर्क राशि- करियर से जुड़ी किसी समस्या का हल मिलने से युवाओं में उत्साह बना रहेगा। आत्मविश्वास भी व्यक्तित्व को निखारेगा। खर्च करते समय बजट का ध्यान रखें। नौकरी करने वाले लोग स्थानांतरण के लिए जल्दबाजी न करें। अभी धैर्य रखना ठीक है। प्रेमी-प्रेमिका के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 8

कन्या राशि- निजी मामलों में लापरवाही न करें। किसी भी बात पर चर्चा करते समय शब्दों का सही चुनाव करें। आय की स्थिति सामान्य रहेगी, इसलिए खर्चों में संयम रखें। आज कार्यक्षेत्र में कोई नया काम शुरू न करें। अनियमित खानपान की वजह से सिरदर्द और माइग्रेन की परेशानी हो सकती है। भाग्यशाली रंग- केसरिया, भाग्यशाली अंक- 9

वृश्चिक राशि- इस समय ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है। लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे तो सफलता मिलेगी। सूझबूझ और विवेक से काम करेंगे तो अधिकतर स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। माता-पिता का ध्यान रखना और उनका सम्मान करना आपको मन से संतोष देगा। लव- पति-पत्नी के बीच बेहतरीन तालमेल रहेगा। भाग्यशाली रंग- ऑरेंज, भाग्यशाली अंक- 2

मकर राशि- विद्यार्थियों को पढ़ाई और प्रतियोगिता से जुड़े कामों में मनमाफिक सफलता मिल सकती है। ज्यादा सोचने में समय निकल सकता है, इसलिए योजना बनाते ही उस पर काम शुरू करें। कारोबार में कुछ उतार-चढाव बने रहेंगे, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कार्यप्रणाली गोपनीय रखें। आयुर्वेदिक इलाज लाभ देगा। भाग्यशाली रंग- गुलाबी, भाग्यशाली अंक-4

मीन राशि- मेहनत से ही मनमाफिक सफलता मिल सकती है और आत्मविश्वास भी बढेगा। आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। बातचीत के दौरान मर्यादा और शब्दों का ध्यान रखें, नहीं तो कुछ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। सफलता के जोश में गलत लक्ष्य न चुनें। प्रेम संबधों में नजदीकियां बढेंगी। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। भाग्यशाली रंग- क्रीम, भाग्यशाली अंक- 5